सहकारी क्षेत्र में ग्रामीण विकास की असीम संभावनाएं

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

वर्ष : 03 – अंक : 04 – जुलाई 2025

सहकारी शिक्षा का नया युग शुरू

'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी' का भूमि पूजन

'सहकार से समृद्धि' का मंत्र होगा साकार

- शिक्षण प्रशिक्षण
- अनुसंधान व नवाचार
- वैज्ञानिक अप्रोच व मार्केटिंग
- मानव संसाधन का विकास
- सहकारी संस्थान जुड़ेंगे
- डिप्लोमा व डिग्री कोर्स
- सहकारिता के संस्कार पर बल

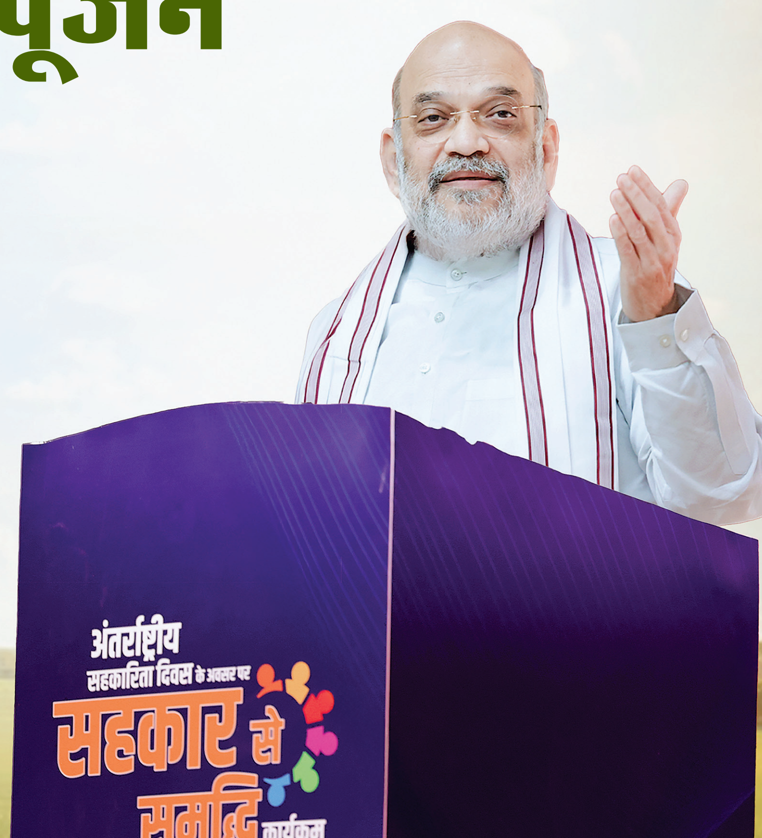

सहकार टैक्सी के प्रमोटर बने आठ सहकारी दिग्गज 27

28 इंश्योरेंस सेक्टर में भी हाथ आजमाएगी कोऑपरेटिव

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

सर्व सहकार सर्व साकार
सहकार जागरण
जुलाई 2025, अंक 04, वर्ष 03

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
डॉ. सुधीर महाजन
संपादक
राजीव शर्मा
समूह संपादक
वेद प्रकाश सेतिया

सहकार जागरण से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें:
sahakarjagran@gmail.com
ncui.pub@gmail.com

प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।
निदेशक (प्रकाशन/जनसंपर्क),
एनसीयूआई
एनसीयूआई कैंपस, 3, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली: 110016

सहकार जागरण से जुड़ने के अन्य पते:

Ministry of Cooperation

NCUI हाट

CEAS-LMS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 'सहकार जागरण' पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है, और इस पत्रिका के प्रकाशन के किसी भी हिस्से की सामग्री की प्रतिलिपि, पुनः उत्पादन या पुनर्वितरण संपादक पैनल और सामग्री के लेखक/लेखकों जैसा भी लागू हो, उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी नहीं कर सकती है। पत्रिका में प्रदर्शित सामग्री तथा आंकड़ें प्राथमिक और अनुषंगी स्रोतों (उद्योग विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि) से लिए गए हैं। पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टों के स्रोतों के संबंध में, न तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और न ही इसके कर्मचारी किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इस संबंध में उनका कोई कानूनी दायित्व है।

05

आवरण कथा

सहकारी शिक्षा का नया युग शुरू

'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी' का भूमि पूजन

सहकारिता क्षेत्र में शिक्षण-प्रशिक्षण और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित की गई देश की पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के साथ ही देश की सहकारी शिक्षा में नया अध्याय लिखने की शुरुआत हो चुकी है।

13

कृषि को बनाना है विकसित भारत का मुख्य आधार

विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कृषि के विकास को समर्थन देने और इसे मजबूत बनाने का एक अनूठा प्रयास है, जिसके तहत वैज्ञानिकों का दल देशभर में किसानों को आधुनिक कृषि के बारे में जानकारी देगा और किसानों की मदद के लिए सभी डेटा उपलब्ध कराएगा।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बन रहा भारत 14

एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग का वैश्विक संकल्प आवश्यक 16

समृद्ध बिहार बनेगा विकसित भारत का आधार 18

स्वास्थ्य समस्याओं के समग्र समाधान पर सरकार का फोकस 20

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भुवनेश्वर में पूर्वी भारत के विकास को दी गति 24

बच्चों को कुपोषण मुक्त और ड्राप आउट अनुपात शून्य करने पर जोर दें राज्य 26

28

इंश्योरेंस सेक्टर में भी हाथ आजमाएगी कोऑपरेटिव

मंथन से निकलेगा सहकारिता का अमृत

सहकारिता पर मंथन से देशभर में सहकारी क्षेत्र में हुई प्रगति, विभिन्न पहलों की उपलब्धियों एवं केंद्रीय योजनाओं को सहकारिता की सबसे छोटी ईकाई 'पैक्स' से लेकर शीर्ष संगठनों (अपेक्स) तक में लागू करने की प्रक्रिया का मंथन किया गया। राज्यों के साथ हुए इस मंथन से सहकारिता का अमृत तलाशने की कोशिश की गई। सहकारिता की प्रगति की समीक्षा और समस्याओं का समाधान पर विशेष चर्ता की गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह की अध्यक्षता में सहकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ हुए गहन विचार विमर्श में मंत्रालय की पहल की समीक्षा की गई। यह पहल वास्तव में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने और इसे नई दिशा देने के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे न केवल देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की योजनाओं को गति मिलेगी, बल्कि अब तक की जमीनीं उपलब्धियों को जांचने-परखने और उन्हें दिशा देने के लिए केंद्र-राज्य सहयोग को भी तेज करेगी। इस मौके पर देश के करोड़ों छोटे किसानों और ग्रामीणों के कल्याण के लिए सहकारिता को पुनर्जीवित करने का संकल्प दोहराया गया और सहकारी क्षेत्र में अपार संभावनाओं का लाभ उठाकर विकसित भारत के निर्माण में भागीदार बनने पर जोर दिया गया।

सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण करके राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला और तहसील स्तर तक की सहकारी संस्थाओं का आंकड़ा पेश किया है, जिससे बहुत ही आसानी से उन स्थानों की पहचान हो रही है, जहां सहकारी तंत्र कमजोर व अनुपलब्ध है। सहकारिता मंत्रालय आगामी पांच वर्षों के भीतर देश के सभी गांवों में कोऑपरेटिव समितियों के विस्तार की योजना पर तेजी से पहल कर रही है और दो लाख नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना की जा रही है।

वास्तव में सहकारिता भारतीय ग्रामीण जीवन का आधार है। प्राचीन समय से ही देशवासियों में सहकार की प्रबल भावना रही है और इसके माध्यम से सभी मिलकर प्रगति और आर्थिक उन्नति की दिशा में प्रयत्न शील रहे हैं। इस विकासमूलक चिंतन को विकसित भारत का मुख्य आधार बनाते हुए भारत सरकार ने चार वर्षों पहले सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। *'सहकार से समृद्धि'* की संकल्पना के साथ सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय ने सहकारी विकास को नई दिशा, ऊर्जा और गति प्रदान की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए 60 से अधिक बेहद ठोस, प्रभावकारी एवं दूरगामी पहल किए हैं, जिससे न केवल सहकारी क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है, बल्कि हमारी सहकारी प्रगति की ख्याति वैश्विक स्तर पर पहुंच चुकी है। अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के वैश्विक महोत्सव का शुभारंभ भारत से होना भी देश में सहकारी प्रगति का एक जीवंत प्रमाण है।

जय सहकार

हमारे किसान भाई-बहनों को पहले जहां छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी उधार लेने को मजबूर होना पड़ता था, वहीं बीते 11 साल में हमारी सरकार के निर्णयों से उनका जीवन बहुत आसान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर किसान फसल बीमा, हमने उनके कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। अब एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी से देश के अन्नदाताओं को न सिर्फ फसलों की उचित कीमत मिल रही है, बल्कि उनकी आय भी बढ़ रही है।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

पूरी दुनिया के लिए सहकारिता एक आर्थिक व्यवस्था है, लेकिन भारत के लिए यह जीवन पद्धति है। पहले केवल शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस तक सीमित रहने वाले प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) आज बहुआयामी होकर सरकार की विभिन्न योजनाओं के केंद्र बन चुके हैं। एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक और बीज की तीन नई सहकारी समितियां एक बड़ी सहकारी शक्ति बनकर उभर रही हैं और किसानों को मजबूत बना रही हैं।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

मोदी सरकार के अथक प्रयास से भारत हर क्षेत्र में भर रहा विकास की नई उड़ान...। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।

श्री कृष्ण पाल गूर्जर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

वर्ष 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी द्वारा शुरू किया गया 'शाला प्रवेशोत्सव अभियान' आज एक मजबूत शैक्षिक आंदोलन बन चुका है। इसके साथ 'कन्या केलवनी' अभियान भी चल रहा है, जो बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देकर सामाजिक जागरूकता को मजबूत करता है।

श्री दिलीप संघाणी
अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहकारिता को भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास की आधारशिला के रूप में देखते हैं। उनका मार्गदर्शक सिद्धांत '*सहकार से समृद्धि*' इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। श्री मोदी का मानना है कि सहकारी संस्थाएं भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं और किसानों, महिलाओं एवं ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने का एक सशक्त माध्यम भी हैं।

सहकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

सहकारी शिक्षा का नया युग शुरू

'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी' का भूमि पूजन

सहकार जागरण टीम

- **सहकारिता आंदोलन में शिक्षण, प्रशिक्षण और नवाचार की कमी को पूरा करने का काम करेगी यह यूनिवर्सिटी, पूरे विश्व में सहकारिता का गढ़ बनेगा भारत**
- **पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुसंधान और सहकारी संघवाद की भावना के विकास के लिए स्थापित हो रही त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी**

सहकारिता क्षेत्र में शिक्षण-प्रशिक्षण और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित की गई देश की पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के साथ ही देश की सहकारी शिक्षा में नया अध्याय लिखने की शुरुआत हो चुकी है। इस यूनिवर्सिटी में युवाओं को तकनीकी विशेषज्ञता, अकाउंटेंसी, वैज्ञानिक अप्रोच और मार्केटिंग के साथ-साथ सहकारिता के संस्कार सीखने को मिलेंगे। यहां से शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को ही सहकारी

संस्थाओं में नौकरी दी जाएगी। गुजरात के आणंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (इरमा) के परिसर में 125 एकड़ में 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी' का भूमि पूजन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इतिहास रच दिया और इसी के साथ यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। सहकारिता राज्य मंत्रियों श्री कृष्णपाल गुर्जर एवं श्री मुरलीधर मोहोल सहित देश के दर्जनों सहकारी दिग्गज इस ऐतिहासिक तारीख के गवाह बने।

इस यूनिवर्सिटी का नाम देश में सहकारिता आंदोलन के संस्थापकों में शामिल त्रिभुवन दास किशिभाई पटेल के नाम पर रखा गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर श्री शाह ने कहा, 'यह दिन सहकारिता क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिभुवन दास पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की नींव पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुसंधान और सहकारी संघवाद की भावना के विकास के लिए डाली गई है। इसके नाम के लिए त्रिभुवनदास पटेल से उचित व्यक्ति कोई नहीं हैं।' इन विचारों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए श्री शाह ने कहा, 'आणंद की धरती से ही श्रद्धेय त्रिभुवनदास पटेल जी ने सहकारिता के माध्यम से गरीबों, महिलाओं और किसानों के जीवन में परिवर्तन की अलख जगाई थी। उनके नाम से स्थापित होने जा रही यह यूनिवर्सिटी युवा शक्ति को सहकार शक्ति से जोड़ने का एक युगांतरकारी प्रयास है। आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय की शाखाएं देश भर में स्थापित की जाएंगी, जहां से प्रशिक्षित युवा सहकारिता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक प्रबंधन के साथ आगे ले जाएंगे।'

सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण को बढ़ावा

वर्ष 2025 संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। इसी वर्ष के दौरान त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए संसद से कानून बनाया जाना और इसके निर्माण की त्वरित प्रक्रिया का शुरू किया जाना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे श्री अमित शाह की ही सोच रही है। इस नाते भी उनके लिए यह चुनौती रही है कि जल्द से जल्द इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य पूरा किया जाए और यहां शिक्षण शुरू किया जाए।

देश के करोड़ों गरीबों और ग्रामीणों के जीवन में आशा का संचार करने और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए चार साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी। अपनी स्थापना के बाद से पिछले 4 साल में सहकारिता मंत्रालय ने भारत में सहकारिता क्षेत्र के विकास, संवर्द्धन और समविकास के लिए 61 नई पहल की हैं। ये सभी पहल सहकारिता आंदोलन को चिरंजीव, पारदर्शी, लोकतांत्रिक बनाने, विकसित करने, सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने और सहकारिता आंदोलन

> आणंद की धरती से ही श्रद्धेय त्रिभुवनदास पटेल जी ने सहकारिता के माध्यम से गरीबों, महिलाओं और किसानों के जीवन में परिवर्तन की अलख जगाई थी। उनके नाम से स्थापित होने जा रही यह यूनिवर्सिटी युवा-शक्ति को सहकार-शक्ति से जोड़ने का एक युगांतरकारी प्रयास है। आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय की शाखाएं देश भर में स्थापित की जाएंगी, जहां से प्रशिक्षित युवा, सहकारिता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक प्रबंधन के साथ आगे ले जाएंगे।
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

स्कूलों के लिए सहकारी शिक्षा मॉड्यूल लॉन्च

भारत के सहकारी आंदोलन के बारे में स्कूली छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के सहयोग से सहकारिता पर एक विशेष द्विभाषी शैक्षिक मॉड्यूल पेश किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के शिलान्यास समारोह के दौरान इस मॉड्यूल का औपचारिक अनावरण किया। हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किए गए इस मॉड्यूल को संवादात्मक, सुलभ और छात्र-अनुकूल बनाया गया है। यह स्कूली पाठ्यक्रम में सहकारी शिक्षा को शामिल करने और युवाओं को सहकारी मूल्यों से परिचित कराने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह मॉड्यूल छात्रों को प्राचीन भारत से सहकारी समितियों की अवधारणा, उनकी संवैधानिक स्थिति, सिद्धांतों और मूल्यों तथा स्वतंत्रता से पहले और बाद में उनकी भूमिका जैसे विषयों से परिचित कराता है। इसमें प्रमुख सहकारी नेताओं, सहकारी समितियों के विभिन्न रूपों और मंत्रालय की हालिया पहलों को भी शामिल किया गया है। सहकारिता मंत्रालय ने कक्षा छह और उससे ऊपर के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में सहकारी विषय शामिल करने और कक्षा 11 और 12 के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में सहकारिता शुरू करने की योजना की भी घोषणा की। इससे छात्र त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से और अधिक जुड़ सकेंगे। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि 'सहकारिता एक विचार नहीं, एक आंदोलन है' का संदेश देश के हर युवा शिक्षार्थी तक पहुंचे।

में मातृशक्ति और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए की गईं। इन्हीं पहल में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना भी शामिल है।

सहकारिता की खामियों को दूर करेगी यूनिवर्सिटी

श्री अमित शाह ने यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के दौरान कहा कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने में रह गई सभी खामियों को पूरा करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में आज देशभर में सहकारिता आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक युगांतकारी कदम है। आज देशभर में 40 लाख कर्मचारी सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हैं, 80 लाख बोर्ड मेंबर हैं और 30 करोड़ लोग, यानी देश का हर चौथा व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। 30 करोड़ सदस्यों वाले सहकारी आंदोलन में शिक्षा, प्रशिक्षण और नवाचार की कमी को पूरा करने का काम यह सहकारी यूनिवर्सिटी करेगी। यह यूनिवर्सिटी नीतियों का निर्माण करेगी, नवाचार को बढ़ावा देगी, अनुसंधान की नींव डालेगी, प्रशिक्षण देगी और देशभर के सहकारी संस्थाओं के प्रशिक्षण का एक समान कोर्स तैयार कर सहकारिता को एकसाथ आगे बढ़ाने का काम करेगी। यह यूनिवर्सिटी प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी और यहीं से सहकारिता की नीति बनेगी, जो सबका मार्गदर्शन करेगी।

कुशल मानव संसाधन की मांग होगी पूरी

श्री शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सहकारिता के कर्मचारियों और सहकारी समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए पहले कोई सुचारू व्यवस्था नहीं थी। पहले कोऑपरेटिव में भर्ती के बाद कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी बनने

के बाद जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, उसी को सहकारी क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। इसके कारण सहकारिता क्षेत्र में भाई-भतीजावाद खत्म हो जाएगा और पारदर्शिता आएगी। सहकारी यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित युवा ही सहकारी संस्थाओं के लिए पात्र होंगे। भारतीय सहकारिता क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन की मांग पूरी करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस यूनिवर्सिटी में युवा तकनीकी विशेषज्ञता, अकाउंटेंसी, वैज्ञानिक अप्रोच और मार्केटिंग के सारे गुण तो सीखेंगे ही, साथ ही उन्हें सहकारिता के संस्कार भी सीखने को मिलेंगे कि सहकारिता आंदोलन देश के दलित, महिलाओं और आदिवासियों के लिए है। सहकारी क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान इस सहकारी यूनिवर्सिटी से हो जाएगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) बनाने का निर्णय लिया है जिनमें से 60 हजार नए पैक्स इस वर्ष के अंत तक बन जाएंगे। 2 लाख पैक्स में ही 17 लाख कर्मचारी होंगे। इसी प्रकार, कई जिला डेयरी बन रही हैं और इन सबके लिए कुशल मानव संसाधन की जरूरत होगी जिसे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी पूरी करेगी। यह यूनिवर्सिटी सहकारिता में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण और देश के कोऑपरेटिव के विकास की 5 साल, 10 साल और 25 साल की रणनीति बनाने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है। यह यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी तैयार नहीं करेगी, बल्कि यहां से त्रिभुवन दास पटेल जैसे समर्पित सहकारी नेता भी निकलेंगे जो भविष्य में सहकारिता क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। श्री अमित शाह ने बताया कि 2 लाख नए और 85 हजार पुराने पैक्स के माध्यम से सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम भी यह विश्वविद्यालय करेगा। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सहकारिता विषय को जोड़ा है। गुजरात सरकार को भी अपने पाठ्यक्रम में सहकारिता विषय को जोड़ना चाहिए जिससे आम लोग सहकारिता के बारे में जान सकें।

सहकारिता भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा

'वसुधैव कुटुंबकम' और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' हमारे देश के मूल विचार और संस्कृति की नींव हैं। उसी से सहकारिता की भावना पैदा हुई है। यह संस्कृति आर्थिक कल्याण के साथ-साथ मानव कल्याण, पशु कल्याण और पर्यावरण को समृद्ध करने के साथ साथ अब गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रही है। 30 करोड़ सदस्यों वाले सहकारी आंदोलन में शिक्षा, प्रशिक्षण और नवाचार के वैक्यूम को भरने का काम यह सहकारी यूनिवर्सिटी करेगी। यह यूनिवर्सिटी नीतियों का निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देगी, अनुसंधान की नींव डालेगी, प्रशिक्षण देगी और देशभर के सहकारी संस्थाओं के प्रशिक्षण का एक समान कोर्स तैयार कर सहकारिता को एकसाथ आगे बढ़ाने का काम करेगी। दो लाख नए और 85 हजार पुराने पैक्स के माध्यम से सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम भी यह विश्वविद्यालय करेगा।

यूनिवर्सिटी से जुड़ें सहकारी विशेषज्ञ

इस यूनिवर्सिटी के बन जाने से न सिर्फ देश का सहकारिता आंदोलन फलेगा, फूलेगा और आगे बढ़ेगा बल्कि पूरे विश्व में भारत सहकारिता का गढ़ बनेगा। त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई जाने वाली नीतियां और अभ्यासक्रम सहकारिता के आर्थिक मॉडल को एक जनआंदोलन में परिवर्तित करने का काम करेंगे। सभी बड़ी सहकारी संस्थाओं के लिए योग्य कर्मचारी प्रदान करने का काम यह यूनिवर्सिटी करेगी। श्री शाह ने कहा कि हम कोऑपरेटिव टैक्सी लाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनाना चाहते हैं, तो हमें हर क्षेत्र

के विशेष ज्ञान वाले अधिकारी, कर्मचारी और सहकारी नेता भी चाहिए। पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि देशभर के सहकारिता प्रशिक्षण विशेषज्ञ इस यूनिवर्सिटी से जुड़ें और अपना योगदान दें।

सभी सहकारी संस्थानों को जोड़ेगी यूनिवर्सिटी

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी में डेयरी, मत्स्य, चीनी, बैंकिंग, ग्रामीण ऋण, सहकारी वित्त, सहकारी मार्केटिंग और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को पाठ्यक्रम में खासतौर पर प्रमुखता दी जाएगी। जिन राज्यों में सहकारी संस्थाओं की अधिकता है उनमें चार से पांच कॉलेजों को सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाएगा और बाकी राज्यों में एक से दो सहकारी कॉलेज इससे संबद्ध किए जाएंगे। इसे वैश्विक स्तर के सहकारी विश्वविद्यालयों और सहकारी संस्थानों से भी संबद्ध किए जाने का प्रावधान किया गया है। सहकारी प्रबंधन संस्थानों को जोड़ने की एक कड़ी होगा। देशभर की स्कूली शिक्षा प्रणाली में इसे शामिल किया जाएगा। इसके पहले चरण में एनसीईआरटी की पुस्तकों के पाठ्यक्रमों में सहकारिता को शामिल किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं के अलग-अलग प्रशिक्षण और प्रबंधन डिप्लोमा व डिग्री कार्यक्रमों का डिटेल तैयार कर लागू करेगा। इसमें पारंपरिक भारतीय आर्थिक दर्शन को समकालीन प्रबंधन तकनीकों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

वैदिक परंपराओं से प्रेरित होकर छात्र इसमें स्थायी कृषि पद्धतियों, नैतिक व्यावसायिक आचरण और समुदाय-संचालित आर्थिक मॉडल के बारे में सीखेंगे। विश्वविद्यालय का एक अन्य उद्देश्य पूरे भारत में सहकारी शिक्षा को मानकीकृत करना है। सहकारी विश्वविद्यालय एक केंद्रीय संस्थान के रूप में भी कार्य करेगा जो आईसीएआर केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों, सीएसआईआर संस्थानों, स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों और अन्य विश्वविद्यालयों से संसाधनों को एकत्रित करेगा। पैक्स सचिवों को भी यहां प्रशिक्षित

त्रिभुवन दास हैं सहकारिता के आदर्श

त्रिभुवन दास पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में आणंद की भूमि पर ही एक नए विचार का बीज बोने का काम किया था। उन्होंने दूध इकट्ठा करने की एक छोटी सी मंडली बनाई और उसके माध्यम से किसानों को सशक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। 1946 में खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना हुई और आज त्रिभुवन दास द्वारा बोया गया वह बीज अमूल के रूप में एक विशाल वट वृक्ष बनकर खड़ा है। इससे 36 लाख महिलाएं जुड़ी हैं और इसका कारोबार 80 हजार करोड़ रुपए का है। आज अमूल विश्व में खाने-पीने की चीजों का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर उभरा है। त्रिभुवन दास पटेल के ही विजन के कारण दुनियाभर की निजी डेयरियों के सामने आज देश की कोऑपरेटिव डेयरी सीना तानकर खड़ी है। श्री शाह ने कहा कि एक सहकारी नेता सहकारिता के हर सदस्य की भलाई के लिए जब काम करता है, तो राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को समृद्ध बनाने की प्रक्रिया में कितना बड़ा योगदान दे सकता है, इसका आदर्श उदाहरण त्रिभुवन दास जी ने प्रस्तुत किया था।

किया जाएगा। पारंपरिक एमएसपी मॉडल से आगे बढ़ाते हुए यह विश्वविद्यालय सहकारी समितियों को बाजार-संचालित समाधान और आत्मनिर्भर व्यवसाय मॉडल अपनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह विश्वविद्यालय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए सहकारी मॉडल विकसित करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे सस्ती चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित होंगी। ■

सहकारिता पर मंथन

सहकारी क्षेत्र में ग्रामीण विकास की असीम संभावनाएं

सहकार जागरण टीम

- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक
- अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में हुई यह बैठक सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर भारत के सहकारिता आंदोलन को नई उड़ान देने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह लगातार प्रयासरत हैं। इस वर्ष के सात महीने बीत चुके हैं और इस दौरान सहाकारिता क्षेत्र को व्यापक विस्तार देने के लिए उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं जिन पर अमल शुरू हो चुका है। इनमें त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना, डेयरी क्षेत्र में तीन नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाने, सहकार टैक्सी की शुरुआत करने और सहकारी क्षेत्र में पूर्ण स्वामित्व वाली बीमा कंपनी बनाने जैसे फैसले शामिल हैं। इस वर्ष केंद्रीय स्तर पर अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के भी चार साल पूरे हो चुके हैं। इन चार वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों और आगे उठाए जाने वाले कदमों को लेकर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ 'मंथन बैठक' की। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इस बैठक का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा, उपलब्धियों का आंकलन और सहयोग को बढ़ावा देना था।

भारत के सहकारी क्षेत्र के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित 'मंथन' बैठक में सहकारी क्षेत्र से जुड़ी नीतियों, नई पहलों एवं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गहन चर्चा हुई। इससे सहकारी विकास के लिए ठोस रणनीति तैयार की जा सकेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और श्री अमित शाह के दूरदर्शी मार्गदर्शन में केंद्र सरकार देशभर की सभी सहकारी संस्थाओं को सशक्त बना रही है, ताकि सहकारी आंदोलन को और मजबूत किया जा सके। यह मंथन बैठक इन्हीं प्रयासों का एक अभिन्न अंग थी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, ''प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना देश में बहुत पुराने सहकारिता के संस्कार को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ नए परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर की है। देश के लगभग 60-70 करोड़ लोग ऐसे थे, जिनके पास जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थीं। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने इन करोड़ों लोगों का जीवनस्वप्न पूरा कर दिया और इन्हें घर,

शौचालय, पीने का पानी, अनाज, स्वास्थ्य, गैस सिलिंडर आदि सुविधाएं प्रदान कर दीं। ये करोड़ों लोग अब अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए उद्यम करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास पूंजी नहीं है। इन करोड़ों लोगों की छोटी-छोटी पूंजी से बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता सहकारिता है।'' भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए दो चीजें बेहद जरूरी हैं। जीडीपी एवं जीएसडीपी का विकास और 140 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना। उन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति के लिए रोजगार के सृजन के लिए सहकारिता के सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसी दूरदर्शिता के साथ सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई।

पांच वर्ष में हर गांव कोऑपरेटिव से जुड़ेगा

देश के करोड़ों छोटे किसानों और ग्रामीणों के कल्याण के लिए सहकारिता क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार किए गए हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री के अनुसार, इसके लिए सहकारिता मंत्रालय ने अब तक 60 से अधिक पहल किए हैं। इन पहलों में से एक महत्वपूर्ण पहल है राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण, जिसकी मदद से सहकारिता क्षेत्र की कमियों को दुरुस्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस इसीलिए बनाया गया है कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तहसील स्तर की सहकारी संस्थाएं मिलकर यह देख सकें कि किस राज्य के किस गांव में एक भी सहकारी संस्था नहीं है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में देश में एक भी गांव ऐसा न रहे, जहां एक भी कोऑपरेटिव न हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उपयोग करने पर श्री शाह ने जोर दिया।

सरकार की पहलों का व्यापक मूल्यांकन

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के व्यापक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, नीति, सुझावों और कार्यान्वयन रणनीतियों के सार्थक आदान-प्रदान की सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के '*सहकार से समृद्धि*' के विजन के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ बैठक में किए गए विचार-विमर्श ने समावेशी विकास को प्राप्त करने में आपसी सहयोग और समन्वय के महत्व को रेखांकित किया। चर्चा के मुख्य बिंदुओं में देशभर में दो लाख बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एमपैक्स) की स्थापना की प्रगति और ग्रामीण सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देना शामिल था। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के कार्यान्वयन पर भी बैठक के दौरान विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में भाग ले रहे प्रतिनिधियों ने 'सहकारिता में सहकार' दृष्टिकोण के तहत अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में अपने योगदान को भी सामने रखा।

शिक्षण-प्रशिक्षण से बदलेगी सहकारिता की दिशा

देश में सहकारिता आंदोलन के पिछड़ जाने के पीछे तीन मुख्य कारण हैं। पहला, समय के साथ कानून नहीं बदले गए जिसे अब बदल दिया गया है। दूसरा, सहकारिता में अन्य गतिविधियों को नहीं जोड़ा गया या समय के साथ बदलाव नहीं किया गया। तीसरा, पहले सहकारिता क्षेत्र में सारी भर्तियां भाई-भतीजावाद से होती थीं। इसमें सुधार लाने के लिए ही त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। श्री शाह ने राज्यों के सहकारिता मंत्रियों से आग्रह किया कि हर राज्य की कम से कम एक सहकारी प्रशिक्षण संस्था त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े, ताकि राज्य के कोऑपरेटिव सेक्टर की ट्रेनिंग की समग्र व्यवस्था इसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो। सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण से युक्त युवा जब सहकारी संस्थाओं से जुड़ेंगे तो इनका न केवल व्यापक विकास और विस्तार होगा, बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होने से युवा इसमें अपना करियर भी बना सकेंगे।

> मोदी सरकार राज्यों को साथ लेकर निरंतर सहकारी क्षेत्र को उन्नति और समृद्धि की ओर ले जा रही है। केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा करने वाली है। हर राज्य राष्ट्रीय नीति के तहत स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द सहकारिता नीति बनाएं। साथ ही, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से जुड़कर सहकारी प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दें।
>
> **श्री अमित शाह**
>
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

जल्द आएगी नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय नई राष्ट्रीय सहकारी नीति लाने पर भी काम कर रहा है। श्री शाह ने बैठक में बताया कि जल्द ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल जनवरी में यह नीति घोषित हो जाएगी। यह नीति वर्ष 2045 तक अमल में रहेगी। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के तत्वावधान में ही हर राज्य की सहकारिता नीति वहां की सहकारिता की स्थिति के अनुरूप बनाई जाएगी और इसके लक्ष्य भी निर्धारित किए जाएंगे। पूरे देश में सहकारिता के क्षेत्र में अनुशासन, नवाचार और पारदर्शिता लाने का काम इस मॉडल एक्ट से होगा। केंद्र सरकार का प्रयास है कि आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत एक आदर्श कोऑपरेटिव देश बन जाए। श्री शाह ने राज्यों के सहकारिता मंत्रियों से कहा कि दो लाख बहुउद्देशीय पैक्स के निर्माण के निर्णय के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लक्ष्य को फरवरी महीने में ही हासिल कर लिया जाए, तभी हम दो लाख पैक्स के लक्ष्य तक समय से पहुंच सकेंगे। ■

आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे पैक्स

सहकार जागरण टीम

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए इनका कंप्युटरीकरण किया जा रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने अब 80,000 पैक्स का कंप्युटरीकरण करने का लक्ष्य रखा है। पैक्स के डिजिटलीकरण के बाद इन्हें समावेशी, जीवंत, निर्बाध और कुशलतापूर्वक कार्य करने लायक बनाया जाएगा। इसके लिए इन्हें उभरती टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, ताकि किसानों और ग्रामीणों को इनके माध्यम से हर तरीके की सुविधाएं मिल सकें। केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने 'पैक्स में उभरती प्रौद्योगिकियों' पर आयोजित एक कार्यशाला में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'हमारे किसानों और ग्रामीणों को मौसम संबंधी, आपदा संबंधी, वर्षा पूर्वानुमान, कीट हमले संबंधी सलाह की आवश्यकता है। आज ऐसी नई तकनीकें उपलब्ध हैं, जिन्हें हमारे ग्रामीण भारत को जागरूक और मजबूत बनाने के लिए सिस्टम से जोड़ा जा सकता है।

पैक्स कंप्युटरीकरण योजना में अब तक लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब लक्ष्य 80,000 पैक्स का कंप्युटरीकरण करना और भारत सरकार की सभी योजनाओं को पैक्स के साथ एकीकृत करके उन्हें जीवंत आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं में बदलना है।' पैक्स डिजिटलीकरण के लाभों की तुलना रेलवे के कंप्युटरीकृत टिकट प्रणाली से करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण से पैक्स की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता आएगी तथा यह अपने अस्तित्व के लिए व्यवहार्य और बड़े पैमाने पर समाज के लिए मूल्यवान बन जाएगा। पैक्स में भारत सरकार के लिए 'वन स्टॉप शॉप' बनने की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। हमें बस यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पैक्स अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाएं।

पैक्स को समावेशी, जीवंत और निर्बाध, कुशलतापूर्वक और पारदर्शिता के साथ कार्य करने योग्य बनाने के लिए उभरती टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा

आज पैक्स की अल्पावधि ऋण सुविधाओं के माध्यम से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई है। इससे पता चलता है कि पैक्स जैसी संस्थाएं ग्रामीण भारत के छोटे और सीमांत किसानों की सेवा करके स्पष्ट रूप से लाभकारी रही हैं। देश में करीब 2,000 बैंकिंग लाइसेंस में से 1,900 लाइसेंस सहकारी क्षेत्र में हैं और 100 लाइसेंस अन्य बैंकों के पास हैं। सबसे छोटी ऋण संरचनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ये नई तकनीक को अपनाने में अक्षम रहीं हैं, जिसके कारण सीमित बैंकिंग उत्पादों के साथ सहकारी बैंकों के कामकाज पर कुछ स्तर तक प्रतिबंध हैं।

सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र के बैंकिंग मुद्दों को आरबीआई, वित्त मंत्रालय और आयकर विभागों के साथ उठाया गया। अब समय आ गया है कि सहकारी बैंकिंग संरचना नई तकनीकों को अपनाए, अपने संचालन में पारदर्शिता लाए और अपने मानव संसाधन मुद्दों को हल करके खुद को प्रतिस्पर्धी बनाए। सहकारिता सचिव ने कहा कि पहले पैक्स केवल ऋण या कृषि के लिए सामग्री प्रदान करने के लिए थे।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने पैक्स को मजबूत करने और समाज के लिए उनकी भूमिका बढ़ाकर उन्हें व्यवहार्य बनाने का फैसला किया। पैक्स को सक्षम करने के लिए मॉडल बायलॉज बनाए गए, ताकि वे दो दर्जन से अधिक कारोबारी गतिविधियों में खुद को विविधता प्रदान करके आगे की आकांक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ जीवित रह सकें। सहकारिता मंत्रालय ने चार साल की छोटी सी अवधि में सहकारिता के विभिन्न आयामों से जुड़ी 60 से अधिक पहल की हैं।

इस कार्यशाला में डिजिटल इंडिया के युग में पैक्स, सटीक कृषि उपकरणों का लाभ उठाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और इंटरनेट टेक्नॉलाजी, कोऑपरेटिव फिनटेक और नीतिगत नवाचार तथा तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और मिजोरम में सफलता की कहानियों पर भी चर्चा की गई।■

विकसित कृषि संकल्प अभियान में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कृषि को बनाना है विकसित भारत का मुख्य आधार

सहकार जागरण टीम

विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों के लिए प्रगति के नए रास्ते खोलेगा और कृषि में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा

विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कृषि के विकास को समर्थन देने और इसे मजबूत बनाने का एक अनूठा प्रयास है, जिसके तहत वैज्ञानिकों का दल देशभर में किसानों को आधुनिक कृषि के बारे में जानकारी देगा और किसानों की मदद के लिए सभी डेटा उपलब्ध कराएगा। इन विचारों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान देशवासियों से साझा किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों के 2,000 दल देश के 700 से अधिक जिलों का दौरा करेंगे और सुदूर के गांवों तक के लाखों किसानों से संपर्क कर उन्हें खेती की विभिन्न उपयोगी जानकारियां प्रदान करेंगे। जब वैज्ञानिकों के दल प्रयोगशाला से खेतों तक जाएंगे और किसानों के बीच व्यापक डेटा पहुंचाने के साथ उन्हें कृषि से जुड़े उन्नत ज्ञान से अवगत कराकर किसानों की सहायता करेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए राज्यों और किसानों के सहयोग से कृषि प्रणालियों में आधुनिक सुधार लाना जरूरी है। उन्होंने कृषि के परंपरागत रूप से राज्य का विषय होने का जिक्र करते हुए कहा कि देश के सभी राज्यों के किसानों के कल्याण के लिए नीतियां बनाने और नई पहल करने पर सरकार का फोकस है। देश में रिकॉर्ड फसल उत्पादन और अनाज के भंडारों के भरे होने पर खुशी जताते हुए उन्होंने किसानों को सचेत किया कि बाजार का स्वरूप और उपभोक्ता प्राथमिकताएं लगातार बदल रही हैं। देश के कृषि वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण रिसर्च और प्रगति का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों के नवीन खोजों ने खेती के परिणामों पर सकारात्मक असर डाला है। उन्होंने देश के उन प्रगतिशील किसानों की तारीफ की जिन्होंने नई तकनीकों को खेती में अपनाकर सफलता हासिल की है और प्रभावशाली पैदावार के जरिए समृद्धि की ओर बढ़े हैं। श्री मोदी ने कहा, ''विकसित कृषि संकल्प अभियान इस ज्ञान के अंतर को पाटने का एक मूल्यवान अवसर प्रस्तुत करता है, जिससे किसानों को अत्याधुनिक कृषि से जुड़ी जानकारियों से लाभ मिल सके।''

700

से अधिक जिलों का दौरा करेंगी वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों की 2,000 टीमें

उन्होंने कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने, किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने, कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और देश की जरूरतों के हिसाब से फसल उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देकर कहा, ''भारत को न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, बल्कि वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में भी उभरना चाहिए।'' जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना, न्यूनतम जल उपयोग के साथ अनाज उत्पादन को बढ़ाना, हानिकारक रसायनों से मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, कृषि तकनीकों का आधुनिकीकरण करना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को खेतों तक ले जाना आवश्यक है। पिछले 10-11 वर्षों में सरकार ने इन क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए हैं। श्री मोदी ने कहा, ''विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत के किसानों के लिए प्रगति के नए रास्ते खोलेगा, कृषि में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा।'' ■

नई दिल्ली में राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों के सम्मेलन में बोले श्री अमित शाह

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बन रहा भारत

- **आपदा प्रबंधन में क्षमता, दक्षता, गति और सटीकता के क्षेत्र में मोदी सरकार ने हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां**
- **बिपरजॉय तूफान में जीरो कैजुअल्टी यह दर्शाती है कि केंद्र, राज्य, स्थानीय इकाई, वैज्ञानिक, सुरक्षाकर्मी और जनता मिलकर बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं**
- **'मिनिमम कैजुअल्टी' के लक्ष्य पर चलते हुए मोदी सरकार ने 11 वर्षों में 'जीरो कैजुअल्टी' के लक्ष्य को प्राप्त कर दुनिया को आश्चर्य में डाला**

सहकार जागरण टीम

ग्लोबल वार्मिंग व बढ़ते प्रदूषण के कारण आज पूरी दुनिया विभिन्न प्रकार के आपदाओं से जूझ रही है। वहीं, भारत आपदा से निपटने और इसके समग्र प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में अग्रसर है और इस मामले में भारत को दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में अग्रसर करने का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों को जाता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन तथ्यों को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों के वार्षिक सम्मेलन में व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि भारत के डिजास्टर रिस्पांस के इतिहास में मोदी सरकार के पिछले वर्षों को एक परिवर्तनकारी दशक के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस दौरान भारत ने आपदाओं से निपटने के मामले में क्षमता, गति, दक्षता और सटीकता के चारों क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आपदा प्रबंधन की अपनी क्षमता को न सिर्फ बढ़ाया है, बल्कि उसे तहसील स्तर तक पहुंचाने का काम भी किया है। इसमें नेशनल डिजास्टर

जीरो कैजुअल्टी के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आपदा प्रबंधन के मामले में भारत के दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन आया है। सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के राहत केंद्रित दृष्टिकोण को बदलकर इसे समग्र और एकीकृत बनाया है, जिससे भारत जीरो कैजुअल्टी के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि आपदाओं का सटीक पूर्वानुमान और उससे बचाव के उपाय को लागू करना बहुत अहम है। मोदी सरकार ने आपदा से निपटने के प्रयासों को 'रिएक्टिव' की जगह 'प्रोएक्टिव' बनाया है और जन-भागीदारी को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र के साथ राज्य सरकारें और स्थानीय इकाइयां मिलकर आपदाओं का सामना करने के लिए आगे आ रही हैं। हमने एक कदम आगे बढ़ते हुए इन मामलों में समाज को भी जोड़ने का कार्य किया है, जिससे भविष्य में लोगों की भागीदारी और बढ़ेगी।

68

हजार करोड़ रुपए से राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की स्थापना की गई

मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए), नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ) और कोलिशन फार डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) की महत्वपूर्ण भूमिका है।

श्री शाह ने कहा कि हमने संकट से निपटने में तीव्रता का भी ध्यान रखा है, क्योंकि आपदा के दौरान लोगों को समय पर बचाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। सरकार ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर आपदा मोचन बल को और अधिक कुशल और अपने काम में पारंगत बनाया है। आपदा का सटीक पूर्वानुमान लगाकर और समय पर इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाने और संकट से निपटने में उन्हें भागीदार बनाने में भी सफलता हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वॉर्मिंग ही आपदाओं के मूल कारण हैं। ऐसे में इस खतरे से निपटने की प्रक्रिया में हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ आगे बढ़ना होगा। पर्यावरण संरक्षण के बिना आपदा से शत-प्रतिशत बचाव असंभव है और अगर हम पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे, तो आपदाओं को रोक नहीं पाएंगे।

पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली का विकास एक बड़ी उपलब्धि

श्री शाह ने कहा भारत ने आपदाओं के पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के विकास में बहुत अच्छा काम किया है। इससे हम आपदा से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने में सफल रहे हैं। मोदी सरकार ने 'मिनिमम कैजुअल्टी' के लक्ष्य पर चलते हुए 'जीरो कैजुअल्टी' के लक्ष्य को हासिल कर दुनिया का अचंभे में डाल दिया है। ओडिशा में आए तूफान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में सुपर साइक्लोन में 10 हजार लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वहीं वर्ष 2019 में आए फानी चक्रवात के दौरान सिर्फ एक व्यक्ति की जान गई। इसके बाद गुजरात में आए बिपरजॉय तूफान में हमारी चौकसी ने किसी भी प्रकार की कोई जनहानि और यहां तक कि पशुओं को भी कोई नुकसान नहीं होने दिया। इससे साबित हो गया कि अगर सरकार व सभी एजेंसियां मिलकर काम करें और जनता की भी भागीदारी हो, तो हर प्रकार के खतरे से सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है।

श्री शाह ने कहा कि आपदाओं से निपटने में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ) और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एसडीआरएफ) की बहुत अहम भूमिका रही है। हमारी सरकार ने अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में इन एजेंसियों को सशक्त करने का काम किया है और इसके लिए इनका बजट बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जहां वर्ष 2004 से 2014 तक एसडीआरएफ का बजट 38 हजार करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2014 से 2024 के बीच बढ़ते एक लाख 44 हजार करोड़ रुपए हो गया। इसी प्रकार, एनडीआरएफ का बजट वर्ष 2004 से 2014 तक 28 हजार करोड़ रुपए था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाकर 84 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि 68 हजार करोड़ रुपए से राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की स्थापना की गई है। इन कदमों के चलते भारत ने आपदा से निपटने में गांव स्तर तक सफलता हासिल की है।

आपदाओं से निपटने में बढ़ रही जन भागीदारी

आपदा से निपटने में जनभागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए श्री शाह ने कहा कि हमने एक लाख 'कम्युनिटी वॉलंटियर्स' तैयार किया है, जिसमें 20 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसके साथ ही सरकार ने 'युवा आपदा मित्र योजना' भी बनाई है। उन्होंने सभी राहत आयुक्तों को तीन महीने के भीतर अपने-अपने राज्यों के हर जिले में ज़िला आपदा प्रबंधन योजना बनाने का निर्देश दिया, जिससे संकट के समय आपदाओं से सफलतापूर्वक निपटना सुनिश्चित हो सके। श्री शाह ने जल्द ही आकाशीय बिजली की कार्य योजना बनाने पर भी जोर दिया और अग्निशमन सेवाओं के विस्तार व आधुनिकीकरण में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने 'हीट वेव' से निपटने के लिए भी एक एक्शन प्लान बनाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि अंतराज्यीय मॉक ड्रिल को हम वार्षिक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए राज्यों को भी आगे आना होगा। श्री शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत 'जीरो कैजुअल्टी' के दृष्टिकोण के साथ और आगे बढ़ेगा। ■

विशाखापत्तनम में बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी

एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग का वैश्विक संकल्प आवश्यक

- **योगांध्रा अभियान में दो करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए, जो जन भागीदारी की जीवंत भावना को दर्शाता है**
- **योग सब के लिए है और हमें विश्व के साथ एकरूपता की दिशा में ले जाता है**

सहकार जागरण टीम

योग एक ऐसा जन आंदोलन है जो विश्‍व को शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव की ओर ले जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन का आरंभ योग से करे, जिससे जीवन में संतुलन आए। प्रत्येक समाज को तनाव से मुक्त होने के लिए योग को अपनाना चाहिए। संपूर्ण मानव समाज और विश्व कल्याण के लिए इन प्रेरक विचारों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह के दौरान व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'योग को मानवता को एक सूत्र में पिरोने का काम करना चाहिए, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग को वैश्विक संकल्प बनना चाहिए।' योग का सार 'एकजुट होना' है और यह देखना उत्साहजनक है कि योग ने विश्‍व को कैसे एकजुट किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह 11वां अवसर है जब विश्‍व 21 जून को सामूहिक रूप से योग का अभ्यास करने के लिए एकत्रित हुआ है।

इस वर्ष अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम, ''एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग'' का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह एक गहन सत्य को दशार्ती है कि पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का स्वास्थ्य परस्पर जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, ''योग हमें सिखाता है कि हम अलग-थलग व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। शुरुआत में, हम अपने स्वास्थ्य और कल्याण की देखभाल करना सीखते हैं, लेकिन धीरे-धीरे, यह देखभाल हमारे पर्यावरण, समाज और पूरे विश्‍व तक फैल जाती है। योग एक गहन व्यक्तिगत अनुशासन है जो एक सामूहिक प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है, यह व्यक्तियों को 'मैं' से 'हम' में रूपांतरित करता है।''

विश्‍व भर में जीवनशैली का अभिन्न हिस्‍सा बना योग

पिछले एक दशक में योग की यात्रा का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के विचार का प्रस्ताव रखा था और विश्व के 175 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। यह व्यापक वैश्विक एकता का एक दुर्लभ उदाहरण है। इसने मानवता की भलाई के लिए दुनिया भर के सामूहिक प्रयास का प्रतिनिधित्व किया। इन वर्षों में योग विश्‍व भर

मन, शरीर और मस्तिष्क में एकात्मता लाता है योगः श्री शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के अवसर पर अहमदाबाद, गुजरात में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया। योग को दैनिक जीवन का अंग बनाने की अपील करते हुए श्री शाह ने सोशल मीडिया पर अपने विचारो को साझा किया और कहा कि मन, शरीर और मस्तिष्क में एकात्मता लाने वाला 'योग' आज विश्वभर में लोगों की दिनचर्या का अंग बन चुका है। योग सदियों से स्वस्थ और आरोग्य जीवन पद्धति वाली भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। नियमित योगाभ्यास शरीर, मन और विचारों को विकारों से मुक्त बनाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अमूल्य धरोहर 'योग' को पूरे विश्व ने अपनाया है।

में लाखों लोगों की जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बन गया है। प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए कहा कि अब दिव्यांग लोग व्यक्ति ब्रेल में योग संबंधी पुस्तकें पढ़ रहे हैं और वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग का अभ्यास कर रहे हैं।

विशाखापत्तनम को प्रकृति और प्रगति का संगम बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि योगांध्रा अभियान में दो करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए हैं, जो जन भागीदारी की जीवंत भावना को दर्शाता है और यही भावना विकसित भारत का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति हमें 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' (सभी सुखी हों) का मूल्य सिखाती है। यही सोच सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है।

चिकित्सा पद्धति के रूप में भी योग विज्ञान लाभकारी

भारत में आधुनिक शोध के माध्यम से योग के वैश्विक प्रसार को बढ़ाने और योग विज्ञान को सुदृढ़ करने के प्रयासों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान योग अनुसंधान में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। इस दिशा में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने अनुकरणीय योगदान दिया है। योग ने हृदय और तंत्रिका संबंधी विकारों के उपचार के साथ-साथ महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदर्शित किया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से योग और स्वास्थ्य के संदेश को पूरे देश में सक्रियतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। इस प्रयास में डिजिटल तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योग पोर्टल और योगांध्रा पोर्टल के माध्यम से देश भर में दस लाख से अधिक कार्यक्रम पंजीकृत किए गए हैं और भारत के हर कोने में योग कार्यक्रम इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं।

''हील इन इंडिया'' मंत्र की वैश्विक लोकप्रियता को देखते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योगाभ्यास को मानकीकृत करने के लिए एक सामान्य योग प्रोटोकॉल विकसित किया गया है। योग प्रमाणन बोर्ड ने 6.5 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया है और लगभग 130 संस्थानों को मान्यता दी है। मेडिकल कॉलेजों में 10-दिवसीय योग मॉड्यूल को शामिल किया गया है। देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रशिक्षित योग शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। वैश्विक समुदाय को इसका लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने विशेष ई-आयुष वीजा के प्रावधान की घोषणा की। ■

बिहार में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

समृद्ध बिहार बनेगा विकसित भारत का आधार

सहकार जागरण टीम

- **नई वैशाली-देवरिया रेलवे लाइन और मुजफ्फरपुर और बेतिया के रास्ते पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी**
- **नमामि गंगे परियोजना के तहत 1800 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन**

बिहार का एक समृद्ध इतिहास रहा है जो कई सदियों तक भारत की प्रगति की अगुआई की है। लेकिन पिछली सरकारों के दौरान यह विकास की राह से भटक गया था जो एक बार फिर विकास की राह पर चल पड़ा है। एक समृद्ध बिहार ही विकसित भारत की नींव बनेगा। यह विचार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के सीवान में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए साझा किया।

श्री मोदी ने कहा कि बिहार के महापुरुषों के विकसित बिहार के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है और उसके लिए कार्य कर रही है। यह कार्यक्रम भी उसी का एक हिस्सा है। ये परियोजनाएं सीवान, सासाराम, बक्सर, मोतिहारी, बेतिया और आरा जैसे क्षेत्रों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाएंगी और गरीबों, वंचितों, दलितों, महादलितों, पिछड़े और अति पिछड़े समुदायों के जीवन को आसान बनाएंगी।

आने वाले समय में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की इसमें अहम भूमिका होगी। बिहार के लोगों की ताकत और क्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा, ''एक समृद्ध बिहार देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।'' बिहार के लोग स्वाभिमानी हैं, अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते और अपनी कर्मठता के चलते विपरीत हालात में भी सफल होते हैं। चुनौतियों के बावजूद नीतीश कुमार के बिहार को विकास के पथ पर वापस लाने पर प्रधानमंत्री

ने उनकी सराहना की। पिछले 10-11 वर्षों में बिहार में लगभग 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। 1.5 करोड़ से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए, जबकि 1.5 करोड़ घरों को नल का जल मिला है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य भर में 45,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो इस बात का प्रमाण हैं कि अब बिहार के छोटे शहरों में नए स्टार्ट-अप उभर रहे हैं।

देश में गरीबी उन्मूलन के नारे लंबे समय से सुने जा रहे हैं, लेकिन गरीबी कम करने का दायित्व राजग सरकार ने पूरा किया है। पिछले एक दशक में रिकॉर्ड 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से उबारा गया है। इसमें नीतीश सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले दस सालों में बिहार में करीब चार करोड़ लोगों ने गरीबी को मात दी है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश में बड़ी संख्या में लोग अब भी गरीबी का दंश झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान गरीबों को घर नहीं मिला। वे राशन से वंचित रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। रिश्वत व सिफारिश के बगैर नौकरियां मिलना असंभव था। इससे सबसे ज्यादा दलित, महादलित, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े समुदायों के लोग प्रभावित हैं।

गरीबों के मार्ग से हर बाधा को दूर करने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में देश भर में चार करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को उनकी सरकार की ओर से पक्के घर प्रदान किए गए हैं। आगामी वर्षों में अतिरिक्त तीन करोड़ घरों का निर्माण किया जाना है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयास से बिहार के गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े परिवारों को काफी लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अकेले बिहार में 57 लाख से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं और यह काम बिना किसी रुकावट के चल रहा है। उन्होंने इस बात पर विशेष संतोष व्यक्त किया कि इनमें से अधिकांश घर माताओं और बहनों के नाम हैं। जिन महिलाओं के नाम पर कभी संपत्ति नहीं रही, वे अब गृहस्वामिनी बन रही हैं।

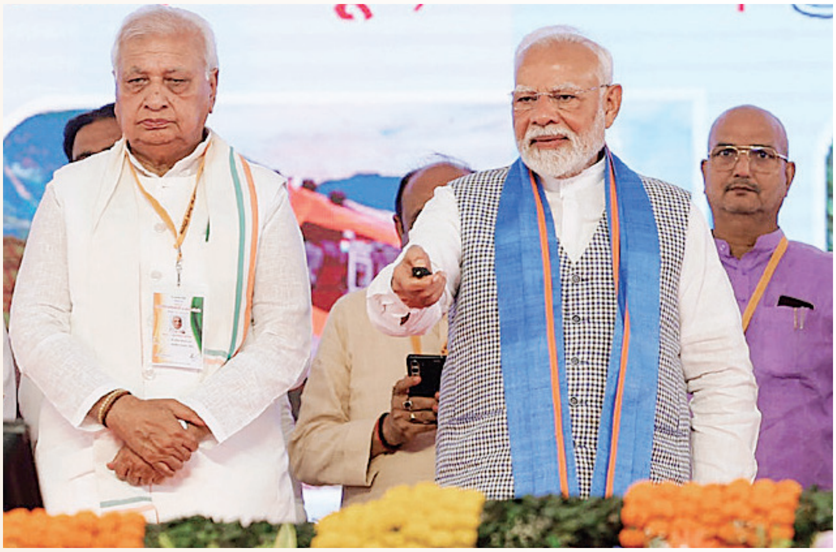

3,000

करोड़ रुपए से अधिक लागत की जलापूर्ति, स्वच्छता और एसटीपी परियोजनाओं की रखी आधारशिला

सरकार गरीबों को न केवल आवास बल्कि मुफ्त राशन, बिजली और पानी की सुविधा भी प्रदान कर रही है। हाल के वर्षों में 12 करोड़ से अधिक नए घरों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में बिहार के विभिन्न शहरों में कई पाइपलाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि अब बड़ी संख्या में नए शहरों के लिए नई पाइपलाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी गई है।

एनडीए के विकास मॉडल का उल्लेख करते हुए उन्होंने मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित इंजन के निर्यात का हवाला दिया जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि बिहार 'मेड इन इंडिया' विनिर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि न केवल मखाना, फल और सब्जियां जैसे स्थानीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेंगे, बल्कि बिहार के कारखानों में निर्मित सामानों की भी दुनिया भर में मांग बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा, ''बिहार के युवाओं के बनाए गए उत्पाद एक आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करेंगे।''

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में विकसित किए जा रहे आधुनिक बुनियादी ढांचे बिहार की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में सड़कों, रेलवे, हवाई यात्रा और जलमार्गों में अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। बिहार को लगातार नई ट्रेनें मिल रही हैं, जिनमें अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। श्री मोदी ने कहा कि नई पटना-गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन पूर्वांचल में भगवान शिव के भक्तों को आधुनिक यात्रा का विकल्प देगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह ट्रेन भगवान बुद्ध की तपस्थली और उनके महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम भी करती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से न केवल बिहार में औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के विकास से बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और अधिक प्रमुखता से उभरने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके परिणामस्वरूप बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा होंगे। ■

बेंगलुरु में आयोजित समारोह में बोले श्री अमित शाह

स्वास्थ्य समस्याओं के समग्र समाधान पर सरकार का फोकस

सहकार जागरण टीम

- **देश के 60 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दे रही मोदी सरकार**
- **श्री आदिचुंचनगिरी मठ गांव-गांव में स्वास्थ्य केंद्र, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज और बच्चों के लिए शिक्षा के केंद्र चलाने का कर रहा उत्तम कार्य**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसके लिए बहुआयामी विकास योजनाओं को गति देने के साथ-साथ जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करने पर सरकार का विशेष फोकस है। सरकार ने देशवासियों के स्वास्थ्य समस्याओं का 'हॉलिस्टिक अप्रोच' के साथ समाधान किया है। इन विचारों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कर्नाटक में आदिचुंचनगिरी यूनिवर्सिटी (एसीयू) के बेंगलुरु कैंपस के उद्घाटन के दौरान व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के 60 करोड़ गरीबों को पांच लाख रूपए तक का इलाज मुफ्त दे रही है। पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं

एवं सुविधाओं को उन्नत बनाने की दिशा में सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पूर्ववर्ती सरकार के समय तक जहां वर्ष 2014 में देश में सात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) थे, वे आज 23 हो चुके हैं। वहीं, मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 780 हो गई हैं। मोदी सरकार ने देश में चिकित्सा शिक्षा को मजबूत बनाने और देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए एमबीबीएस सीटों को 51 हजार से बढ़ाकर एक लाख 18 हजार कर दिया है और उच्चतर शिक्षा (एमडी व एमएस) की सीटों की संख्या को 31 हजार से बढ़ाकर 74 हजार कर दिया है। इन वर्षों में सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के तहत जन्म से लेकर 15 साल की उम्र तक बच्चों के टीकाकरण की मुफ्त व्यवस्था की और पोषण अभियान के माध्यम से मां एवं बच्चे का पोषण सुनिश्चित कर स्वस्थ नागरिकों के सृजन की शुरुआत की। इसके साथ ही स्वस्थ एवं स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए लगभग 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाए, फिट इंडिया मूवमेंट चलाया और योग दिवस की शुरुआत की। श्री शाह ने कहा कि देशवासियों को सस्ती दवाएं सुलभ कराने के लिए प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना के तहत 15 हजार से अधिक स्थानों पर जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां सरकार ने सभी दवाओं को 80 प्रतिशत तक छूट के साथ केवल 20 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध कराया है।

आदिचुंचनगिरी मठ शिक्षा, सेवा और सामाजिक जागृति को दे रहा विस्तार

श्री शाह ने कहा कि श्री आदिचुंचनगिरी मठ गांव-गांव में स्वास्थ्य केंद्र, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज और बच्चों के लिए शिक्षा केंद्रों के संचालन का उत्तम कार्य कर रहा है। यह एक ओर हमारी परंपरा और संस्कृति से बच्चों और युवाओं को जोड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज में सम्मानीय स्थान दिलाने में भी मददगार है। देश की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में शुमार आदिचुंचनगिरी यूनिवर्सिटी (एसीयू) का बेंगलुरु कैंपस 200 करोड़ रूपए की लागत से 16 एकड़ एरिया में स्थापित हुआ है, जहां चार हजार छात्रों की पढ़ाई के लिए एक संकुल बना है। 1000 बिस्तर वाला यह आधुनिक अस्पताल सभी स्वास्थ्य सुविधाओं, गरीबों के लिए मुफ्त और किफायती दर पर पूरे इलाज और शिक्षा की व्यवस्था के साथ ये संकुल सच्चे अर्थों में सेवा का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। अस्पताल में रिसर्च सेंटर, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और ऑन्कोलॉजी के साथ-साथ किडनी, लिवर और कॉर्निया ट्रांसप्लांट तक की उच्चतम आरोग्य की सेवाएं बहुत कम दर पर और गरीबों के लिए मुफ्त उपलब्ध हैं। जगद्गुरु श्री डॉ. बालगंगाधरनाथ स्वामी जी ने आदिचुंचनगिरी की पवित्र पहाड़ियों में 1800 साल से चली आ रही आध्यात्मिक परंपरा को कायम रखा है और इसके साथ सेवा, शिक्षा और समर्पण को भी जोड़ा है, जिसे डॉ. निर्मलानंदनाथ महास्वामी और आगे बढ़ा रहे हैं। ■

बेंगलुरु में आयोजित समारोह में बोले श्री अमित शाह

हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हों नक्सलवादी

2026

में देश नक्सलवाद से मुक्त होगा

सहकार जागरण टीम

छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पिछले डेढ़ साल में राज्य को नक्सलवाद से मुक्त कराने की दिशा में वे आगे बढ़े हैं। उन्होंने एक रुके हुए नक्सलविरोधी अभियान को द्रुत गति से आगे बढ़ाया है। इन विचारों को छत्तीसगढ़ और पूरे देश से नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए संकल्पित केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में अंतरराज्यीय सुरक्षा समन्वय बैठक और छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा के दौरान व्यक्त किया। श्री शाह ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के डीजीपी, एडीजीपी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रायपुर में सुरक्षा संबंधी अहम बैठकों की अध्यक्षता के दौरान दोहराया कि भारत 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। श्री शाह ने कहा कि जिस तरह से हमारे सुरक्षाबलों ने पराक्रम दिखाया है और सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, उसके आधार पर हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बारिश के मौसम में आराम करने वाले नक्सली इस बरसात में चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, क्योंकि हमारे सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी रहेगा।

- **नक्सली इस बरसात में चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, सुरक्षा बलों का जारी रहेगा ऑपरेशन**
- **सुरक्षा बलों के परिश्रम, त्याग व बलिदान को स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा**
- **मुक्त हुए क्षेत्र में अनाज, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, घर और पीने का शुद्ध पानी पहुंचाकर लाल आतंक का समूल नाश कर रही है सरकार**

सरकार पर भरोसा करें युवा, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों

श्री शाह ने नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर गए सभी युवाओं से हथियार डालकर राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाने का आह्वान किया और कहा कि युवाओं को विकास यात्रा में जुड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिंसा के रास्ते पर चल

श्री शाह ने सुरक्षा बलों के जवानों के साथ किया संवाद

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ संवाद किया। सुरक्षा बलों के साहस, शौर्य, बलिदान और समर्पण की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये जवान अपने शौर्य और परिश्रम से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ को सफल बनाते हैं। सुरक्षा बलों ने जिस शौर्य, धैर्य और समर्पण के साथ माओवादियों के बनाये अड्डों को तहस-नहस किया है, उसने विश्व के सभी सुरक्षा बलों को आश्चर्यचकित कर दिया है। जब नक्सवाद के खात्मे का इतिहास लिखा जायेगा, उसमे सुरक्षा बलों के जवानों के त्याग, बलिदान और परिश्रम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा। श्री शाह ने कहा कि मुझे मालूम है कि सेना के जवान जो तय करते हैं, वह हासिल करते हैं। सुरक्षा बलों के इसी भरोसे से मैं देश में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान करता हूं। नक्सलवाद गरीब आदिवासी क्षेत्र के लिए बड़ी विभीषिका रही है, जिससे पिछले 35 साल में लगभग 40 हजार लोगों की मौत हुई है या फिर लोग अपाहिज होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि नक्सलवादी हिंसा ने गरीब आदिवासी तक खाना, बिजली, शिक्षा, घर, शौचालय और पीने का शुद्ध पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं को नहीं पहुंचने दिया। इतने लंबे वर्षों तक इतना बड़ा क्षेत्र गुलामी के कालखंड में जीने को मजबूर रहा, जिसका मूल कारण नक्लवाद है। उन्होंने कहा कि आज जिस क्षेत्र से नक्सलवाद खत्म

होता है, वहां मोदी सरकार अनाज, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बिजली, घर, शौचालय और पीने का शुद्ध पानी पहुंचाकर लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि जब बच्चा हाथ में बंदूक की जगह पेंसिल पकड़कर क, ख, ग लिखता है, तो न सिर्फ एक क्षेत्र का बल्कि पूरे देश का भविष्य संवरता है। यह क्षण जल्द ही आने वाला है। श्री शाह ने कहा कि जब 31 मार्च, 2026 को देश नक्सलवाद से मुक्त होगा, वो क्षण आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक होगा।

नक्सली हिंसा को बयां करने वाली पुस्तक 'लियोर ओयना' का लोकार्पण

श्री शाह ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नक्सलियों द्वारा आदिवासियों के भीषण संहार और बस्तर को बचाने के प्रयासों पर लिखित पुस्तक 'लियोर ओयना' का लोकार्पण भी किया। नक्सलियों ने जिन मासूम, निहत्थे लोगों को अपनी हिंसा का शिकार बनाया है, उनकी पीड़ा समझने में यह पुस्तक सहायक साबित होगी। यह पुस्तक मानवाधिकारों के नाम पर नक्सलियों से संवेदना दिखाने वालों के आंखों के आगे से पर्दा हटाने और उन्हें एक्सपोज करने में भी उपयोगी सिद्ध होगी। इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि जिन मासूम बच्चों के हाथों में कभी नक्सलियों ने बंदूकें थमा दी थी, आज उनके हाथों में किताबें देकर उनका भविष्य संवारा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की 'लियोर ओयना' योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को रायपुर लाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जा रहा है। इस मौके पर श्री शाह ने बीजापुर के उसूर और गंगालूर विकासखंड के युवाओं से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी किया।

रहे युवा सरकार पर भरोसा करें और समाज की मुख्यधारा में शामिल हों। इस तरह वे अपने आप देश की विकास यात्रा के साथ जुड़ जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों से जो वायदा किया है, उसे पूरा किया जाएगा और उससे अधिक सहायता करने का प्रयास भी किया जाएगा।

नक्सलवाद के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ सरकार के उल्लेखनीय योगदान पर संतोष जताते हुए श्री शाह ने कहा कि राज्य में श्री विष्णुदेव और श्री विजय शर्मा ने नक्सलविरोधी अभियानों को न सिर्फ धार दी, बल्कि समय-समय पर इस अभियान का मार्गदर्शन करके सुरक्षाबलों का हौसला बढ़ाया और नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई में संपूर्णता के साथ बहुत बड़ा योगदान दिया है। ■

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भुवनेश्वर में पूर्वी भारत के विकास को दी गति

सहकार जागरण टीम

- पीएम ने पारादीप से झारसुगुड़ा तक औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार की कही बात
- देश से जल्द ही नक्सलवाद का खात्मा करने का दावा
- मछुआरों के विकास के लिए केंद्र सरकार बना रही 25 हजार करोड़ रुपए का विशेष कोष

ओडिशा केवल एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध विरासत का चमकता सितारा है। इस राज्य ने सदियों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। वर्तमान समय में विकास और विरासत का मंत्र भारत की प्रगति का आधार बन गया है और इसमें ओडिशा समेत पूर्वी भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन विचारों को ओडिशा के भुवनेश्वर में एक समारोह में व्यक्त किया। इस मौके पर श्री मोदी ने 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

ओडिशा के साथ-साथ पूरे पूर्वी क्षेत्र के विकास का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा '21वीं सदी के भारत का विकास पूर्वी भारत से संचालित होगा। यह पूर्वोदय का युग है।' पारादीप से झारसुगुड़ा तक औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा की खनिज और बंदरगाह आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। केंद्र सरकार ओडिशा में सड़क, रेल और हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। पारादीप में मेगा ड्यूल-फीड क्रैकर और डाउनस्ट्रीम इकाई की स्थापना, चांदीखोल में कच्चे तेल भंडारण की सुविधा और गोपालपुर में एलएनजी टर्मिनल जैसी परियोजनाएं ओडिशा को प्रमुख औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित करेंगी। इससे छोटे और मध्यम उद्यमों का विशाल नेटवर्क तैयार होगा और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हाल के वर्षों में ओडिशा के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य 'पेट्रोकेमिकल्स हब' बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान सरकार ने जनसेवा और जनविश्वास के लिए समर्पित सुशासन की स्थापना की है और ओडिशा ने अपनी विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ विकास के मंत्र को पूरे दिल से अपनाया है। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ की इस धरती पर आने के लिए उन्होंने कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में देश ने हमारे विकास मॉडल को देखा है और इसके जरिए लोगों का जीवन आसान हुआ है। सरकार बदलने के साथ ही ओडिशा ने भी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के नए युग में प्रवेश किया है।

विकास के नए पथ पर आगे बढ़ रहा भारत

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दशक पहले अस्थिरता, अलगाववाद और हिंसा से ग्रस्त पूर्वी भारत में उग्रवादी गतिविधियां अब बंद हो गई हैं और यह क्षेत्र भी विकास के नए पथ

18,600

करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

पर आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि असम समेत कई अन्य पूर्वी राज्य अब विकास के कई मापदंडों पर देश के कई अन्य राज्यों से आगे निकल गए हैं। दशकों से चुनौतियों से जूझ रहे ओडिशा में अब केंद्र और राज्य सरकार के विकास मॉडल का परिणाम दिखने लगा है। केंद्र सरकार की 'आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना' और राज्य की 'गोपबंधु जन आरोग्य योजना' का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों योजनाओं से ओडिशा में करीब तीन करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है।

देश में कमजोर व वंचितों को सशक्त बनाने की बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश भर में 125 से अधिक आदिवासी बहुल जिले नक्सली हिंसा से प्रभावित थे। हाल के वर्षों में उनकी सरकार ने आदिवासी समाज को हिंसा के माहौल से बाहर निकालकर विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ाया है और इससे आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई लहर आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय जल्द ही हिंसा की छाया से मुक्त हो जाएगा और देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा।

आदिवासी क्षेत्रों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता

आदिवासी समुदायों के सपनों को पूरा करना, उन्हें नए अवसर प्रदान करना और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करने को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि पहली बार आदिवासी विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके दो प्रमुख राष्ट्रीय योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से पहली योजना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत देश भर के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। ओडिशा में भी आदिवासी परिवारों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं और सड़कें एवं बिजली और पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य के 11 जिलों में 40 आवासीय विद्यालय भी बनाए जा रहे हैं। वहीं, पीएम जनमन योजना की प्रेरणा भी ओडिशा की धरती से ही मिली है। उन्होंने कहा कि यह योजना आदिवासी समुदाय के भीतर विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के उत्थान पर केंद्रित है।

ओडिशा के मछुआरों के कल्याण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए मत्स्य संपदा योजना तैयार की गई है। मछुआरों को अब किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ भी मिल रहा है। केंद्र सरकार 25 हजार करोड़ रुपए का विशेष कोष स्थापित कर रही है, जिससे ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में रहने वालों को लाभ होगा और युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। ■

मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में बोले श्री अमित शाह

बच्चों को कुपोषण मुक्त और ड्राप आउट अनुपात शून्य करने पर जोर दें राज्य

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे तो क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकारी है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषद सलाहकारी भूमिका से बाहर निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। इन तथ्यों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक के दौरान व्यक्त किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद ही एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय परिषद है जहां दो सदस्य राज्यों के बीच किसी प्रकार की कोई समस्या या विवाद नहीं है और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों एवं सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम के अभिनंदन का प्रस्ताव पेश किया, जिसका परिषद ने ध्वनिमत से अनुमोदन किया। श्री शाह ने कहा कि विश्व की सबसे पौराणिक नगरी वाराणसी से सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसे विकास की नई पहचान दी है। काशी में अद्भुत विकास के माध्यम से उन्होंने हम सभी के सामने यह आदर्श प्रस्तुत किया है कि एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र और जनता के लिए समर्पित भाव से कार्य कर इतना व्यापक बदलाव ला सकते हैं।

वर्ष 2004-14 की तुलना में 2014-25 में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में लगभग 83 प्रतिशत मुद्दों का समाधान किया गया

श्री शाह ने कहा कि जहां वर्ष 2004 से 2014 के बीच जोनल कौंसिल की सिर्फ 11 मीटिंग हुई और स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ जोनल कौंसिल्स की भी 14 मीटिंग्स हुईं, वहीं मोदी सरकार के 11 वर्षों के दौरान जोनल कौंसिल की 28 बैठकें की गईं और स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ जोनल कौंसिल्स के भी 33 मीटिंग हुए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब तक इन बैठकों में 1287 मुद्दों का निराकरण किया गया है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक और उत्साहवर्धक भी है। सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से पिछले ग्यारह वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और इनकी स्थायी समितियों की अब तक कुल 62 बैठकें आयोजित हुईं है।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में राष्ट्रीय महत्व के व्यापक विषयों सहित कुल 19 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इनके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन, प्रत्येक गांव के नियत दायरे में ब्रिक-एंड-मोर्टार बैंकिंग सुविधा और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का कार्यान्वयन जैसे बहुत से मुद्दे शामिल रहे। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषद के सभी राज्य बच्चों में कुपोषण दूर करने, ड्रॉप-आउट रेश्यो को जीरो करने और सहकारिता को सुदृढ़ बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सदस्य राज्यों की ग्राम पंचायतों की राजस्व बढ़ाने और इसके लिए नियम बनाने को भी कहा, क्योंकि पंचायतों की राजस्व बढ़ने से ही भारत की त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक पंचायती राज व्यवस्था और अधिक कारगर होगी। ■

सहकार टैक्सी के प्रमोटर बने आठ सहकारी दिग्गज

सहकार जागरण टीम

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इसी साल मार्च में संसद में बताया था कि ओला और उबर की तरह जल्द ही सहकारी टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी। मोबाइल ऐप आधारित इस टैक्सी सेवा के शुरू होने से न केवल ग्राहकों को विकल्प मिलेगा, बल्कि टैक्सी चालकों को सशक्त बनाकर सहकारी उद्यमिता को बढ़ावा देने और सहकारिता क्षेत्र का विस्तार करने में भी यह मददगार साबित होगा। उनकी यह घोषणा अब मूर्त रूप लेने जा रही है। इसके लिए सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नाम से एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उम्मीद की जा रही है कि सहकारिता के माध्यम से देश की पहली टैक्सी सेवा की शुरुआत इसी वर्ष दिसंबर में हो जाएगी। देश के परिवहन क्षेत्र के लिए यह परिवर्तनकारी कदम है।

देशभर की सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने वाली राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) इस सहकारी समिति की मुख्य प्रमोटर है, जबकि देश की प्रमुख सहकारी संस्थाएं अमूल, नैफेड, नाबार्ड, इफको, कृभको, एनडीडीबी और एनसीईएल अन्य प्रमोटर हैं। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड को 300 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया गया है। प्रत्येक प्रमोटर ने प्रारंभिक चरण में 10 करोड़ रुपए का योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई है।

'सहकार' ऐप से होगी बुकिंग

यह सहकारी समिति दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में शुरुआती परिचालन करेगी। बाद में इसका विस्तार देश के बाकी हिस्सों में किया जाएगा। सहकारी टैक्सी सेवा के ऐप आधारित प्लेटफॉर्म का नाम 'सहकार' होगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहक टैक्सी के अलावा दोपहिया, ई-रिक्शा और अन्य चार पहिया वाहन भी बुक कर सकेंगे। सहकार टैक्सी की सबसे बड़ी विशेषता इसका सहकारी ढांचा है, जिसमें टैक्सी चालक न केवल सेवा प्रदाता होंगे, बल्कि सहकारी समिति के सह-मालिक भी होंगे। यह मॉडल चालकों को निष्पक्ष लाभ वितरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी और बेहतर कार्यस्थितियों का अवसर प्रदान करेगा। सहकार टैक्सी को केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं चलाया जाएगा, बल्कि यात्रियों से उचित किराया लिया जाएगा और लाभ का बड़ा हिस्सा ड्राइवरों में समान रूप से बांटा जाएगा। ड्राइवरों की सामाजिक सुरक्षा का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। इसका स्वामित्व और प्रबंधन पूर्ण रूप से इसके सदस्यों, यानी टैक्सी चालकों के हाथों में होगा। यह सहकारी मॉडल पारदर्शी और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देगा। इस पहल का मूल मंत्र '*सहकार से समृद्धि*' है, जो सहकारी मूल्यों पर आधारित समावेशी और टिकाऊ परिवहन सेवाओं को सुनिश्चित करता है।

अंतरिम बोर्ड गठित

सहकारी टैक्सी सेवा के प्रारंभिक परिचालन की देखरेख के लिए एक अंतरिम बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष एनसीडीसी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गुप्ता हैं। बोर्ड के अन्य प्रमुख सदस्यों में वी. श्रीधर (एनडीडीबी), तरुण हांडा (नैफेड), नवीन कुमार (नाबार्ड), संतोष शुक्ला (इफको) और एलपी गॉडविन (कृभको) शामिल हैं। इस सेवा के लिए मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए तकनीकी भागीदारों से बातचीत शुरू हो चुकी है। इसे तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए आईआईटी बेंगलुरु जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही है। यह सहयोग उद्योग मानकों के अनुरूप तकनीकी विकास, परिचालन प्रणालियों और डिजिटल एकीकरण को सुनिश्चित करेगा। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड न केवल उपभोक्ताओं को सस्ती, कुशल और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करेगा, बल्कि यह टैक्सी चालकों के लिए एक टिकाऊ और समावेशी आजीविका मॉडल भी स्थापित करेगा। यह पहल सहकारी समितियों के बीच सहयोग के सिद्धांत को मजबूत करते हुए परिवहन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगी, जो प्रौद्योगिकी, समावेशिता और सहकारी मूल्यों पर आधारित होगा।

सहकार टैक्सी यात्रियों से उचित किराया लिया जाएगा, सरचार्ज और टिप जैसी वसूली नहीं होगी। शुरुआती चरण में लगभग 400-500 ड्राइवरों को इस सेवा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। छह महीने की सेवा के बाद प्रत्येक ड्राइवर 100 रुपए के पांच शेयर खरीदकर सहकारी समिति के सदस्य बन सकेंगे। ■

इंश्योरेंस सेक्टर में भी हाथ आजमाएगी कोऑपरेटिव

सहकार जागरण टीम

- **बीमा क्षेत्र में कोऑपरेटिव का हिस्सा बढ़ा कर जल्द ही पूर्ण स्वामित्व वाली इंश्योरेंस कंपनी बनाई जाएगी**
- **नैफेड के नए उत्पाद, एफपीओ को अनुदान और गोदाम बनाने के लिए पैक्स के साथ अनुबंध को दिया गया औपचारिक रूप**
- **किसानों को समृद्ध बनाने और उनके समर्थन में एक सशक्त इकोसिस्टम खड़ा करने के लिए की गई सहकारिता मंत्रालय की स्थापना**

सहकारिता क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने और इसका विस्तार व्यापक स्तर पर करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में अब पूर्ण स्वामित्व वाली सहकारी बीमा कंपनी की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में मुंबई में नैफेड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में इसकी घोषणा की। इस साल अब तक सहकारी क्षेत्र के लिए यह चौथी बड़ी पहल है। इससे पहले देश की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाने, कोऑपरेटिव टैक्सी सेवा की शुरुआत करने और डेयरी क्षेत्र में तीन नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाने की पहल सहकारिता मंत्रालय द्वारा की जा चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की '*सहकार से समृद्धि*' की परिकल्पना को साकार करने में ये पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

नैफेड की राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा, 'सरकार ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना का निर्णय लिया है और जल्द ही इसका भूमिपूजन हो जाएगा। कोऑपरेटिव मॉडल

पर टैक्सी सेवा की भी शुरुआत होगी, जिसमें टैक्सी ड्राइवर सिर्फ इससे जुड़ा नहीं होगा, बल्कि वह इसमें मालिक की भूमिका में होगा और मुनाफा सीधा उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। साथ ही, बीमा क्षेत्र में कोऑपरेटिव का हिस्सा बढ़ा कर जल्द ही पूर्ण स्वामित्व वाली इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत होगी। इससे कई नए आयाम खुलेंगे।' अभी देश की सहकारी संस्थाओं में से सिर्फ इफको ही बीमा क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन उसका संयुक्त उद्यम है। इस उद्यम का पूर्ण स्वामित्व उसके पास नहीं है। श्री शाह की घोषणा के अनुसार अब जो बीमा कंपनी बनेगी उसका पूर्ण स्वामित्व सहकारी संस्थाओं के पास ही होगा। इसका खाका कैसा होगा, इसमें कौन-कौन सी सहकारी संस्थाएं होंगी, नई सहकारी कंपनी सामान्य बीमा क्षेत्र (जीआईसी) की होगी या जीवन बीमा क्षेत्र (एलआईसी) की, इस बारे में अभी फैसला किया जाना बाकी है। नई सहकारी बीमा कंपनी बनने से सहकारिता आंदोलन का और विस्तार होगा और इसे नई मजबूती मिलेगी।

इस कार्यक्रम में नैफेड के नए उत्पाद, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को अनुदान और गोदाम बनाने के लिए नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के साथ अनुबंध को औपचारिक रूप दिया गया, जो नैफेड की किसान लक्षित गतिविधि का परिचायक है। श्री शाह ने कहा कि नैफेड ने सफलता की ढेर सारी गाथाएं रची हैं। किसान खेत में अपना पसीना बहा कर अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर भारत सरकार को देते हैं और वही अनाज गरीबों को हर महीने 5 किलो निःशुल्क राशन के तौर पर दिया जा रहा है। इस पूरी योजना की रीढ़ एनसीसीएफ और नैफेड हैं। नैफेड के ऐप पर किसान अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, तो उनकी सौ प्रतिशत दाल और मक्का नैफेड एमएसपी पर खरीद लेगा। मॉडल ऐप की सफलता को देखते हुए नैफेड आने वाले दिनों में किसानों से सीधी खरीद की शुरुआत करने वाला है। इस व्यवस्था से किसान अपनी फसलों की प्लानिंग अच्छी तरह कर सकता है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर तीन सहकारी संस्थाओं राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना से किसानों की उपज को वैश्विक बाजार में बेचने में मदद मिलेगी जिससे इनका मुनाफा किसानों के खाते में जाएगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को भारत ब्रांड के साथ भारत ऑर्गेनिक के नाम से विश्व और देश के बाजार में बेचने से परंपरागत और जैविक खेती करने वाले किसानों को फायदा तो होगा ही, साथ ही उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी मिल पाएगा। श्री शाह ने कहा कि बीजों के संरक्षण और संवर्द्धन के साथ हम इनकी उत्पादकता बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि दस साल बाद ये तीनों नए राष्ट्रीय कोऑपरेटिव अमूल, नैफेड, इफको, कृभको की तर्ज पर किसानों के लिए बहुत बड़ी कोऑपरेटिव संस्था बनेंगे।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने बताया कि लगभग सभी पैक्स का कंप्युटराइजेशन किया जा चुका है। इनमें से लगभग 52,000 पैक्स लाइव हो चुके हैं। पैक्स को 24 अलग-अलग प्रकार के काम करने की अनुमति देकर उन्हें व्यावहारिक बनाया गया है। केवल कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से ही पैक्स अब 300 विभिन्न योजनाओं के केंद्र बन चुके हैं। कंप्युटराइजेशन के बाद सारी अकाउंटिंग सिस्टम उनके कंप्यूटर में राज्य की स्थानीय भाषा में उपलब्ध करा दी गई है। सहकारिता मंत्रालय ने तकनीक में सुधार के लिए भी ढेर सारा काम किया है। इसमें सबसे अहम आयकर कानून में कॉरपोरेट और कोऑपरेटिव को समान स्तर पर लाना है। अधिभार को 12 प्रतिशत से घटा कर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। मैट 18.5 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया। 2 लाख रुपए से कम के लेनदेन पर आयकर जुर्माने से भी पैक्स को मुक्ति देने का काम किया गया है। साथ ही, सहकारी चीनी मिलों के टैक्स विवाद को भी सुलझा दिया गया है।

सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता एनसीडीसी के माध्यम से दी गई है। मछली पालन में 44 गहरे समुद्री ट्रॉलर कोऑपरेटिव के माध्यम से दिया जा रहा है। साथ ही, श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से डेयरी सेक्टर को भी मजबूत किया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि भारत सरकार ने किसानों को मक्के के उचित दाम दिलाने के लिए मक्के से बनाए इथेनॉल के दाम भी बढ़ाए हैं। आज मक्के से बने इथेनॉल का पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक उपयोग किया जा रहा है। इसके कारण देश का आयात बिल बहुत कम हुआ है। आने वाले दिनों में डेयरी क्षेत्र में सर्कुलर इकनोमी को भी बढावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री शाह ने कहा कि हमारा देश सिर्फ जीडीपी के आधार पर सशक्त नहीं हो सकता। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जीडीपी तो बढ़नी ही चाहिए, परन्तु सभी को रोजगार भी मिलना चाहिए। गांव के गरीबों, युवाओं और महिलाओं को रोजगार युक्त करना है, तो केवल सहकारिता ही एक ऐसा साधन है जो बहुत कम पूंजी में ढेर सारे लोगों को व्यवसाय के साथ जोड़ता है और कम पूंजी में ज्यादा मुनाफे के मंत्र को साकार करता है। ■

विशेष आलेख

श्री दिलीप संघाणी

सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने में एनसीयूआई की अहम भूमिका

भारत में सहकारी आंदोलन की एक समृद्ध और प्रभावशाली परंपरा रही है। इसने विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था में व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में वर्तमान में 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 29 करोड़ देशवासियों की सदस्य के रूप में सहभागिता है। ये समितियां कृषि उत्पादन, ग्रामीण वित्त, आवास, मार्केटिंग, उपभोक्ता सेवा, डेयरी सेक्टर, मत्स्य पालन और अन्य उद्योगों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। लेकिन, इसके बावजूद सहकारी क्षेत्र को सुशासन, नवाचार, प्रशिक्षण की कमी और तकनीकी पिछड़ापन जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने और इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए समय-समय पर नए कदम उठाए जाते रहे हैं। इन चुनौतियों को दूर करने और सहकारी आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। यह ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उनके '*सहकार से समृद्धि*' के दृष्टिकोण के अनुरूप लिया और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह को देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में दायित्व प्रदान किया। मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र में बुनियादी सुधारों और दूरगामी नीतियों को लागू किया गया है। श्री शाह के कुशल नेतृत्व में सहकारी क्षेत्र में जो युगांतकारी अभिनव पहल किए गए हैं, उनमें तीन राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं जैसे जैविक उत्पादों के निर्यात, बीज क्षेत्र और बहुउद्देश्यीय सेवाओं के लिए राष्ट्रीय समितियों के गठन इत्यादि शामिल हैं। इन संस्थाओं के जरिए सहकारी समितियों को वैश्विक बाजार तक पहुंच, बेहतर बीज गुणवत्ता और जैविक कृषि को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय एक परिवर्तनकारी पहल

सरकार ने सहकारी शिक्षा और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 'राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय' की स्थापना की है। यह विश्वविद्यालय सहकारी प्रशासन, नेतृत्व, उद्यमिता, डिजिटल प्रबंधन, और नीति-निर्माण जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों और सहकारी कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा। इसका उद्देश्य न केवल सहकारी क्षेत्र की पेशेवर क्षमताओं को मजबूत करना है, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करना है। सहकारी विश्वविद्यालय के माध्यम से सहकारी बैंक, विपणन संघ, आवास समितियों, कृषि सेवा समितियों और अन्य क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन की मांग को पूरा किया जा सकेगा।

लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) पोर्टल का शुभारंभ

सहकारी शिक्षा के डिजिटलीकरण के लिए एक महत्त्वपूर्ण पहल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल प्रधानमंत्री श्री मोदी के तकनीकी रूप से सशक्त भारत और आत्मनिर्भर सहकारिता की परिकल्पना का अहम हिस्सा है। इसके जरिए सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को तकनीकी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षण को आसान, आकर्षक और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनाना है। इसके माध्यम से युवा, सदस्य, कर्मचारी और उद्यमी सहकारी प्रबंधन, शासन, लेखा, लेखा परीक्षण, कानूनी प्रक्रियाओं, और सामाजिक उद्यमिता जैसे विषयों की गहन जानकारी एवं विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। ये प्रयास भारत के सहकारी आंदोलन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह पोर्टल केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि संवाद और समाधान केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। इसके जरिए प्रशिक्षु अपने सवालों के समाधान के लिए विशेषज्ञों से त्वरित सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इससे निर्णय लेने की दक्षता और व्यावसायिक कौशल में वृद्धि होती है।

एलएमएस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को बहुत से लाभ मिल सकते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्र आसानी से एक साथ वे डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इससे सहकारी संस्थाओं में प्रशिक्षकों, सलाहकारों और प्रबंधकों की मांग में वृद्धि होती है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। यह पोर्टल सहकारी स्व-रोजगार और उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। यह पहल 'आत्मनिर्भर भारत' और 'डिजिटल इंडिया' जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है। इससे सहकारी समितियां वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास को गति मिलेगी। ■

अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको

राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई) ने नई दिल्ली में नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारतीय मत्स्य सहकारी समितियों के शीर्ष पदाधिकारियों को सरकारी योजनाओं, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और मत्स्य व्यवसाय में प्रौद्योगिकी-संचालित डिजिटलीकरण के बारें में तकनीकी जानकारी दी गई। एनसीयूआई की उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए।

मत्स्य पालन क्षेत्र में सहकारी शासन को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई) ने देश भर के मत्स्य पालन सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम संपन्न किया, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 46 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की और सहकारी मूल्य, नई सहकारी नीति, एमएससीएस अधिनियम और सदस्यता प्रक्रियाओं की बारीकियों को समझा।

'सहकारिता और सहकारी प्रबंधन' को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) ने इफ्को की फूलपुर इकाई के टेक्नोक्रेट्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जमीनी स्तर पर सहकारी नेतृत्व को मजबूत करने और सहकारी व्यवस्था को सरल बनाने के लिए प्रबंधकीय क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया।

सहकारी सूचना अधिकारियों (सीआईओ) को सहकारी समितियों के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देने के लिए एनसीयूआई ने तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रशिक्षुओं को नई जिम्मेदारियों के प्रदर्शन में क्षमता निर्माण और समितियों में पारदर्शिता बनाए रखने की ट्रेनिंग दी गई। यह कार्यक्रम सीआईओ की वैधानिक और नियामक ढांचे के बारे में समझ को बढ़ाने पर केंद्रित रहा।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 समारोह के हिस्से के रूप में देश भर में हो रहे सहकारी आयोजनों के क्रम में पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में मिजोरम महिला सहकारी संघ (वुमनफेड) लिमिटेड ने आरसीएस कॉन्फ्रेंस हॉल में वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया, जिसमें सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) ने भागीदारी करके सहकारी विकास को गति देने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को मनाने और देश में सहकारिता को आगे बढ़ाने के क्रम में बिहार की राजधानी पटना में दशरथ मांझी संस्थान में राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य, हर पहलू में आगे रहना है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। शिक्षा, संगठन और औद्योगिक प्रगति से समाज कल्याण के विजन की स्पष्ट छाप आज हम देश की नीतियों और निर्णयों में भी देख सकते हैं। इससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। हमने सेवा को संकल्प बनाया, जिसका परिणाम है कि आज देशभर के करोड़ों परिवारों को पीएम आवास से लेकर बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।

- श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

एनसीयूआई हाट, एनसीयूआई और कम प्रचलित सहकारी संस्थाओं के बीच नये आयाम स्थापित कर रहा है, जो उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। अब एनसीयूआई हाट अपने नवीन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी *'सहकार से समृद्धि'* को साकार करने के लिए उपर्युक्त वातावरण का निर्माण कर रहा है।

CEAS-LMS Portal

कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (CEAS-LMS) अपने तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सहकारी सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देता है। यह तीन चरण में काम करता है:

1. **LMS:** लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रत्येक चरण की सहकार शिक्षा दी जाती है।
2. **QMS:** क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता सहकारिता से जुड़े अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत गुणवत्ता परक सलाह मिल सके।
3. **CRC:** कोऑपरेटिव रिर्सोस सेंटर सभी हितधारकों का प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य जानकारियों का आदान प्रदान कर सके।

https://ncuicoop.education/

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए राजीव शर्मा द्वारा प्रकाशित और एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मुद्रित। संपादक: राजीव शर्मा

Postal Registration No: DLHIN/25/A0141
Published on 15.04.2024 Applied for Registration/ Exempted

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ